

3 **बस्तर संभाग**  
जहां नहीं है सड़क वहां पंचायत ने बना दिया लाखों रुपये का पुलिया

6 **अभिमत**  
उर्वरक उद्योग की भूमिका पर सवाल

10 **संस्कारधानी**  
मुहों से दूर प्रत्याशियों की छवि पर ही लगेगी मुहर...

11 **न्यायधानी**  
निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का धरना प्रदर्शन...



रायपुर, लखनऊ, नई दिल्ली और फरीदाबाद से प्रकाशित

हमेशा सच के साथ

RNI NO. CHHHIN/2016/70655

# प्रायोजक

www.dailypioneer.com रायपुर, शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 पृष्ठ-12 वर्ष-06, अंक- 118 मूल्य 3.00 ₹



## विवेक न्यूज

तबलीगी जमात, निजामुद्दीन मरकज पर प्रतिबंध लगाया जाय : विहिप

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने तबलीगी जमात व उसके निजामुद्दीन मरकज को इस्लामिक कट्टरपंथ की फैक्ट्री और वैश्विक आतंकवाद का पोषक बताते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विहिप की ओर से गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञापन में विहिप के कार्यध्यक्ष आलोक कुमार ने बयान दिया कि तबलीगी जमात के कृत्य विश्व के लिए गम्भीर खतरा है। उन्होंने इस पर सऊदी सरकार द्वारा लागू गए प्रतिबंध का स्वागत करते हुए कहा कि लोगों का जीवन संकट में डालने वाले तबलीगी जमात के आर्थिक श्रोतों का पता लगाकर उसके बैंक खातों, कार्यालयों व कार्यकलापों पर भारत सरकार सम्पूर्ण विश्व समुदाय द्वारा अबिलम्ब प्रतिबंध लगाया जाए।

दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामलों की पुष्टि

नई दिल्ली। राजधानी में गुरुवार को कोरोना वायरस से नए स्वल्प ओमिक्रॉन से संक्रमित चार और नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में ओमिक्रॉन से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गयी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

## महिलाओं के विवाह की उम्र 21 वर्ष करने का प्रस्ताव, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

वार्ता < नई दिल्ली  
www.dailypioneer.com

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की विवाह की उम्र मौजूदा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन

किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि महिलाओं में कुपोषण की समस्या को देखते हुए सरकार इस योजना पर काम कर रही है कि उनका विवाह सही उम्र में हो। महिलाओं की विवाह की उम्र कम करने के लिए सरकार को मौजूदा



कानून में संशोधन करना होगा और इसके लिए संसद में विधेयक लाया जायेगा। अभी देश में पुरुषों की विवाह

की उम्र 21 वर्ष जबकि महिलाओं के विवाह की उम्र 18 वर्ष है।  
**सरकार ने दी मंजूरी** - अब सरकार देश की लड़कियों को सशक्त करने के लिए उनकी शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कैबिनेट में मिली मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006,

विशेष मैरिज एक्ट और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसी एक्ट में संशोधन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट में कमी लाना चाहती है। कहा जा रहा कि बेटियों की शादी 21 साल की उम्र में करने से उनकी अपनी पढ़ाई और डेवलपमेंट का भी मौका मिलेगा।

## पिछले साल सौंपा गया था प्रस्ताव

सरकार ने पिछले साल जून में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने साल 2020 में ही शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समता पार्टी की पूर्व सदस्य और टास्क फोर्स की प्रमुख जया जेटली ने इसकी सिफारिश की थी। साथ ही टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में लड़कियों के मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपनी सिफारिश दी थी।

## विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

एजेंसी < नई दिल्ली  
www.dailypioneer.com

विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में गुरुवार को गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफा की मांग को लेकर भारी हंगामा किया जिसके कारण पीठासीन अधिकारी भर्तिहरि महताब को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। एक बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दो बजे जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कणमण, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबा कर रहे सदस्यों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं जिसमें 'श्री

मिश्रा इस्तीफा दो' और 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिश्रा का इस्तीफा लो' लिखा हुआ था। विपक्ष के शोर शराबे के बीच श्री महताब ने मंत्रालयों और संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात सभा पटल में रखवाए। हंगामे के बीच ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैव विविधता विधेयक 2021 को पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने बार-बार विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर लौट जाने का आग्रह किया लेकिन शोर मचा रहे सदस्यों पर उनके आग्रह का कोई असर नहीं हुआ। सदन में गतिरोध बढ़ता देख हुए श्री महताब ने कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।



रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक पहुंचे खरीदी केंद्र। जालबांधा थान खरीदी केंद्र में ग्राम पेटे और पवनतरा के किसानों से खरीदी की जानकारी ली।

## देश के लिए गोलियां झेलने वाली इंदिरा का नाम नहीं, सच से डरती है सरकार : राहुल

एजेंसी < नई दिल्ली  
www.dailypioneer.com

1971 के युद्ध में भारत की जीत को याद करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार इंदिरा को क्रेडिट नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सच से डरती है, इसलिए विजय दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उनका नाम नहीं लिया गया। इससे पहले नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि कुछ लोग इंदिरा गांधी को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश युद्ध को लेकर दिल्ली में एक आयोजन हुआ। इसमें इंदिरा गांधी

के नाम का जिक्र नहीं किया गया। जिस महिला ने देश के लिए 32 गोलियां झेलीं, उनका नाम आमंत्रण में नहीं था, क्योंकि यह सरकार सचवाई से डरती है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंकरक्षकों ने कर दी थी। इससे पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ लोग इंदिरा गांधी के काम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोग आज के दिन को याद करते हैं। जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा तक लोकतंत्र की मदद के लिए योगदान करते आए हैं, लेकिन कुछ लोग 1971 के योगदान को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं।

## प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए लोगों की राय लें : सुप्रीम कोर्ट

वार्ता < नई दिल्ली  
www.dailypioneer.com

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली और इसके आसपास इलाकों में 'खतरनाक' स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए तात्कालिक उपायों पर संतोष व्यक्त किया और इसके स्थायी समाधान के लिए विशेषज्ञों एवं आम लोगों की राय लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से दिल्ली और इसके

आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के स्थायी समाधान की तलाश के लिए आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया। पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आयोग के कदमों पर संतोष व्यक्त किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण के मामले में अगली सुनवाई फरवरी के प्रथम हफ्ते में की जाएगी। सर्वोच्च अदालत 17 वर्षीय स्कूली छात्र आदित्य टुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

## सुप्रीम कोर्ट 'वज्रियार' समुदाय आरक्षण पर सुनवाई को सहमत

उच्चतम न्यायालय गुरुवार को तमिलनाडु में अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत वज्रियार समुदाय को 10.5 फीसदी आरक्षण देने के मामले में विचार करने के लिए सहमत हो गया। शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार की ओर से वज्रियार को आरक्षण देने संबंधी कानून को मद्द्दास उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई को सहमत हुई। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरा की शीर्ष अदालत की पीठ ने संबंधित पक्षों को जोड़ित कर जवाब तलब किया है।

## सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर

एजेंसी < श्रीनगर  
www.dailypioneer.com

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से बुधवार देर रात रेडवानी बाला में घेराबंदी तथा तलाश अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि तलाश अभियान के दौरान वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा



बलों के जवानों ने गोलियां चलाईं और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। उल्लेखनीय है कि पड़ोसी जिला पुलवामा में कल ही आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मुठभेड़ में मारा गया था।

## सड़कों और भवनों के नये नाम रखे जाने चाहिए : राजनाथ

एजेंसी < नई दिल्ली  
www.dailypioneer.com

जाना चाहिए जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सिंह ने गुरुवार को यहां रक्षा संपदा महानिदेशालय के नाम बदलकर उन चीजों, साहसी तथा सेनानायकों के नाम पर रखने पर विचार किया

कार्यक्रम में यह सुझाव दिया।

# 3 साल बेमिसाल

## उत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान. भूपेश बघेल जी के शानदार 3 साल उपलब्धियों भरे कार्यकाल की हार्दिक बधाई

## गुजरात में यह जन आंदोलन बन चुका है वहीं हिमाचल में भी बढ़ा है आकर्षण

## प्राकृतिक खेती को जन आन्दोलन बनायें : मोदी

वार्ता < नई दिल्ली  
www.dailypioneer.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर कृषि की अत्यधिक निर्भरता को समाप्त कर मामूली खर्च वाली प्राकृतिक खेती को देश को जन आन्दोलन बनाने का आह्वान किया है। मोदी ने गुजरात के आणंद में तीन दिन के प्राकृतिक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन किसानों के सम्मेलन को आनलाइन सम्बोधित करते हुए गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को जन आन्दोलन बनायें तथा जिले में कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ें। गुजरात में यह जन आन्दोलन बन गया है और हिमाचल प्रदेश में भी इसका आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में



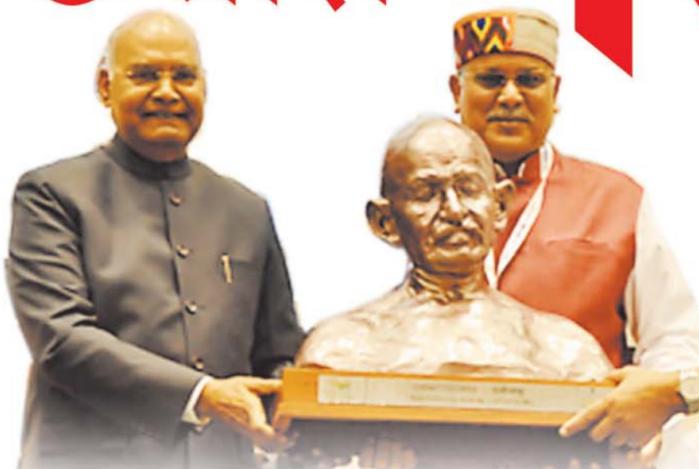
खाद्य सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती का आज बेहतर समन्वय करने तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त कृषि का संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में जैविक और प्राकृतिक खेती के उत्पादों के प्रसंस्करण में निवेश की अपार संभावना है तथा विश्व बाजार ऐसे उत्पादों का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों

में हजारों किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और अनेक स्टैंट अप भी इस क्षेत्र में आ गये हैं। किसानों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज खेती को केमिकल लैब से प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती विज्ञान आधारित है और इससे जमीन की उर्वराशक्ति बढ़ती है।

मोदी ने खेती के संबंध में प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के फ्रेम में डालने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे जुड़े ज्ञान को शोध या सिद्धांत तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। ऐसी जानकारी को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। मोदी ने प्राकृतिक खेती को देसी गाय आधारित बताते हुए कहा कि इसके गोबर और मूत्र से मिट्टी की ताकत बढ़ती है और फसल की सुरक्षा भी होती है। इसमें खाद और कीटनाशक पर खर्च नहीं होता है और सिंचाई की भी कम जरूरत होती है। यह पद्धति बाढ़ और सूखे से भी निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरक ने हरितक्रांति में अहम भूमिका निभायी है लेकिन इसके विकल्प पर भी काम करते रहना होगा।

# अवार्डों का छातीसगाढ़

**3 साल बेमिसाल**



## 2021

- दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार : 3 दिसंबर 2021
- सफ़ाई मित्र सुरक्षा चैलेंज - 2021 श्रेणी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड का खिताब छत्तीसगढ़ के नाम : 21 नवंबर 2021
- छत्तीसगढ़ को मिला देश का सबसे स्वच्छतम राज्य का अवार्ड : राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्रहण किया स्वच्छता अवार्ड : 20 नवम्बर 2021
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार : 23-09-2021
- प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में मिला द्वितीय पुरस्कार : 17-09-2021
- लघु वनोपजों के संग्रहण में मॉडल राज्य के रूप में उभरा छत्तीसगढ़, देश में सर्वाधिक 11 पुरस्कारों से छत्तीसगढ़ को केन्द्रीय मंत्री द्वारा नवाजा गया : 27 अगस्त 2021
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2021 : छत्तीसगढ़ को मिला 12 पुरस्कार : 24-04-2021
- छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कारों में दूसरा स्थान : 21-04-2021
- हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में छत्तीसगढ़ को मिला पुरस्कार : 14-04-2021
- प्रदेश की पंचायतों ने फ़िर दिखाया दम, लगातार तीसरे साल 11 राष्ट्रीय पुरस्कार : 03-04-2021
- राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021: कोण्डागांव को मिला दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार : 01-04-2021
- राजनांदगांव के ग्राम खुटेरी की जय मां दुर्गा महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित : 08-03-2021
- बिलासपुर जिले को पीएम किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिला राष्ट्रीय अवार्ड : 24-02-2021
- मोर जमीन-मोर मकान में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिला पुरस्कार : 01-01-2021
- बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को मिला पुरस्कार
- बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल श्रेणी में डोंगरगढ़ को मिला इनाम
- बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में हितग्राहियों को मिला पुरस्कार

## 2020

- केन्द्र सरकार ने बिलासपुर और सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड के लिए किया चयनित : 28-10-2020
- सर्वाधिक ओडीएफप्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा पुरस्कार : 2 अक्टूबर 2020
- छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार : 20-08-2020
- मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाईल एप को राष्ट्रीय पुरस्कार : 11 जुलाई 2020
- छत्तीसगढ़ को मिला ई-पंचायत पुरस्कार : 23 जून 2020
- छत्तीसगढ़ की तीन पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार : 02 मई 2020
- कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ़ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को ई-गवर्नेंस अवार्ड : 17 जनवरी 2020
- बेमेतरा को मिला स्वच्छता दर्पण अवार्ड : आमिर खान के हाथों कलेक्टर शिखा राजपूत ने ग्रहण किया पुरस्कार : 12 जनवरी 2020
- देश के 115 आकांक्षी जिलों में से दन्तेवाड़ा को सुपोषण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मिला सिल्वर स्कोच अवार्ड : 11 जनवरी 2020
- सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार : 02 जनवरी 2020

## 2019

- मनरेगा, आजीविका मिशन, आवास योजना और पीएमजीएसवाई में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 22 पुरस्कार : 19 दिसम्बर 2019
- धान की दुर्लभ किस्मों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार : 24 अक्टूबर 2019
- जनपद पंचायत नगरी को मिला पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार : 24 अक्टूबर 2019
- पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर कांकेर जिला पुरस्कृत : 23 अक्टूबर 2019
- राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में छत्तीसगढ़ को मिले 11 पुरस्कार : 23 अक्टूबर 2019
- छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार, बच्चों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल मित्र

पंचायत पुरस्कार : 24 सितम्बर 2019

- ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 9 राष्ट्रीय पुरस्कार : 20 सितम्बर 2019
- कांकेर जिला को मिला स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार : 09-09-2019
- लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए रायगढ़ जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित : 06 सितम्बर 2019
- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बी.पी. मण्डल सामाजिक न्याय रत्न सम्मान से किया गया सम्मानित : 25 अगस्त 2019
- पोषण अभियान में उल्लेखनीय कार्य : छत्तीसगढ़ को मिले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार : दो श्रेणियों के तहत उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिला दूसरा स्थान : मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दी बधाई : 23 अगस्त 2019
- छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य : राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया ने प्राप्त किया सम्मान : 06 मार्च 2019
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर सुधार के फलस्वरूप कोण्डागांव जिला देश में प्रथम : ओवरऑल रैंकिंग में देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों में मिला दूसरा स्थान : 06 मार्च 2019
- पहली बार निर्वाचन में छत्तीसगढ़ को मिले सर्वाधिक चार राष्ट्रीय पुरस्कार : 25 जनवरी 2019
- निर्वाचन में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू को मिला राष्ट्रीय सम्मान : 25 जनवरी 2019
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर रायगढ़ जिले को मिला राष्ट्रीय सम्मान : 24 जनवरी 2019
- छत्तीसगढ़ की तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार : 07 जनवरी 2019

**3 साल बेमिसाल**

**मान. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हृदय से आभार...**

**प्रमोद मिश्रा** जून अध्यक्ष, जून क्र. 09 न. पा. नि. रायपुर

**3 साल बेमिसाल**

बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के

**माननीय भूपेश बघेल जी** मुख्यमंत्री छ.ग. शासन का हृदय से **आभार**

**आशीष शिन्दे** निर्वाचित अध्यक्ष : रायपुर उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस

**3 साल बेमिसाल**

**हमर छत्तीसगढ़ खुशहाल छत्तीसगढ़**

शारिक रईस खान-डायरेक्टर श्रम कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ शासन

अब्दुल हैदर - पूर्व महासचिव प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस

**3 साल बेमिसाल**

बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के

**सतनाम पनाग** पार्षद, वार्ड क्र. 61 न. पा. नि. रायपुर

# जहां नहीं है सड़क वहां पंचायत ने बना दिया लाखों रुपये का पुलिया

पायनियर संवाददाता < नारायणपुर  
www.dailypioneer.com

जिले के अबुलमाड में किस कदर शासकीय राशि का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत द्वारा बंदरबाट किया जा रहा है इसका नजारा कंदाडी ग्राम पंचायत में देखने को मिला। जहां जंगल के बीच खुले मैदान में लगभग 10 लाख रुपये लागत की पुलिया का निर्माण कराया गया है जहां से ना ही कोई सड़क गुजरती, ना ही ग्रामीणों का आना जाना होता है और ना ही वहां किसी प्रकार के नदी नाले का बहाव है। जबकि गांव के अंदर जहां पुलिया की जरूरत थी जहां से रोजाना ग्रामीणों का आना जाना होता है वहां पुलिया का निर्माण ना कराके खुले मैदान में पुलिया का निर्माण करना भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है वहीं जनपद पंचायत अबुलमाड



ओरछा के सीईओ ग्राम पंचायत द्वारा किये गए इस कारनामे पर गोलमोल जवाब देते हुए नक्सलियो द्वारा उक्त मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी के बाद पुलिया निर्माण के बाद सड़क निर्माण कार्य

नहीं होने की बात कही गई। बता दें कि नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर अबुलमाड के ग्राम पंचायत कंदाडी में जंगल के बीचों बीच जहां ना ही सड़क है और ना ही नदी-नाले है वहां पर लगभग

10 लाख रुपये की लागत की आरसीसी पुलिया का निर्माण कर बंदरबाट किया गया जबकि ग्राम पंचायत कंदाडी के गांव के अंदर से गुजरने वाली सड़क पर पुलिया की जरूरत है वहां पर पुलिया का निर्माण

ना कराके जंगल के बीच में पुलिया का निर्माण करना भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। अब ये पुलिया ग्रामीणों के चलने के काम तो नहीं आया पर अब ग्रामीणों के वनोपज सुखाने के काम आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जनपद पंचायत ओरछा के सीईओ रोमांचल यादव ग्राम पंचायत के कारनामों पर पर्दा डालते हुए ग्राम पंचायत कंदाडी द्वारा सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था इसलिए पहले पुलिया का निर्माण किया गया और पुलिया निर्माण के बाद नक्सलियो द्वारा सड़क निर्माण कार्य नहीं कराये जाने की चेतावनी के बाद सड़क निर्माण नहीं किये जाने की बात कही जो अबुलमाड में नक्सलियो के भय के नाम पर किये जा रहे खेल की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है।

# भेलवांपदर वार्ड उपचुनाव में कांग्रेस ने सोरी बाबू के समर्थन में निकाली रैली

एमएल सोरी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम व कांग्रेसी रहे मौजूद

पायनियर संवाददाता < कोण्डगांव  
www.dailypioneer.com

कोण्डगांव नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 भेलवांपदर वार्ड से पार्श्वद रहे मंगल साहू के देहांत होने पश्चात उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एम एल सोरी के पक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम के साथ कांग्रेसियों ने गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील किये।

कहा एम एल सोरी को भेलवांपदर वार्डवासी सोरी बाबू के नाम से पुकारते हैं और सोरी बाबू सदैव जनता के बीच रहकर लोगों की बातें सुनते हैं दिवंगत पार्श्वद मंगल साहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते आये हैं ऐसे



मिलनसार व्यक्तित्व के सोरी बाबू को वार्ड में विजयी बनाने में आपका मत महत्वपूर्ण है ताकि वार्ड के विकास में सोरी बाबू सहयोगी बन सकें रैली के दौरान वार्डवासी मौजूद रहे।

# सरण्डी के व्यापारी से 1837 बोरा धान जब्त

पायनियर संवाददाता < कांकेर  
www.dailypioneer.com

प्रभारी कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य ने बताया कि अंतागढ़ तहसीलदार लोमश कुमार मिरी, खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास तथा थाना प्रभारी ताड़ोकी के संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आज अंतागढ़ के ग्राम सरण्डी के व्यापारी जयराम साहू के गोदाम से 1837 बोरा अवैध धान जब्त कर गोदाम को सील किया गया है। अंतागढ़ के तहसीलदार लोमश मिरी ने बताया कि सरण्डी-ताड़ोकी क्षेत्र में कोचियों के माध्यम से भोले-भाले किसानों से 900 रुपये से 1300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर उपार्जन केन्द्रों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर राजस्व, खाद्य एवं पुलिस विभाग



के अधिकारी-कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा सरण्डी के व्यापारी जयराम साहू के गोदाम पर दबिशा दी गई, जिसमें व्यापारी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा पूछताछ किये जाने पर सही-सही जवाब भी नहीं दिया

गया, जिसके कारण गोदाम में रखे 1837 बोरा धान को जब्त कर सील किया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

पायनियर संवाददाता < कोण्डगांव  
www.dailypioneer.com

जिले में 3 दर्जन से अधिक विभाग कार्यरत हैं वहीं सैकड़ों अधिकारी व कर्मचारी शासन ने नियुक्त कर रखा है। लेकिन वही निर्माण से संबंधित विभागों पर कई सीनियर अधिकारियों के रहते एक ही जूनियर अधिकारी को प्रभार दिया जाना कहीं न कहीं उच्चाधिकारियों के व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है, वहीं जानकारों की मानें तो कई विभागों का प्रभार एक ही अधिकारी को दिए जाने से कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है वहीं निर्माण जैसी तकनीकी कार्य से समझौता होने के बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

विधायक संत नेताम ने भी अपने ही सरकार को घेरा है, सीनियरों के रहते जूनियरों को प्रभार देने के मामले पर-



विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र में 13 व 14 दिसम्बर को ताराकित प्रश्न में अपनी ही सरकार को घेरे हुए वन विभाग व लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के रहते कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देने पर घेरा था, कोण्डगांव जिले में उन्ही के विधानसभा क्षेत्र में कई वरिष्ठ अधिकारियों के रहने के बावजूद कनिष्ठ को प्रभार दिया गया है वह भी एक

विभाग नहीं तीन से ज्यादा विभाग का कार्य एक ही प्रभारी को दिया जाना जिले में चल रहे करोड़ों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के कार्यों पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। मिली जानकारी के अनुसार उप अभियंता सचिन मिश्रा को अनुविभागीय अधिकारी के पद पर आईएस, जिला निर्माण, एसी ट्राईबल के निर्माण शाखा में भी एसडीओ का प्रभार सौंपा गया है।

कई सीनियर बाट जोह रहे निर्माण कार्यों में दायित्व निर्वहन को लेकर जिले में

ज्ञात हो कि जिले में आधे दर्जन से अधिक सीनियर अधिकारी मौजूद हैं जिन से अलग-अलग शाखाओं में दायित्व देकर सफल कार्य संचालन करवाया जा सकता था जिसमें राहुल भगत, भालू प्रताप बंजारे, वीरेंद्र भुआर्य, पीएल सोनवानी, रमेन्द्र समर्थ, रविन्द्र साहू जिले में पदस्थ हैं व नियम भी कहता है कि वरिष्ठता के आधार पर कार्य का प्रभार दिया जावे, लेकिन आला अधिकारियों के चलते सारे नियम शिथिल पड़ गए हैं, वहीं देखने वाली बात है कि जिस विधायक ने शीतकालीन सत्र में अपनी ही सरकार को वरिष्ठता व कनिष्ठता का आड़ना दिखाया था, अपने ही गृह जिले में जिले में चल रहे प्रभार-प्रभार के खेल पर कब तक अंकुश लगाया कार्य विभाजन करवा पाते हैं।

यह एक गंभीर मुद्दा है एक तरफ हमारी सरकार विकास के नए आयाम गढ़ने जा रही है और मेरे ही जिले में अगर इस तरह का मामला मीडिया के माध्यम से सामने आया है तो बिल्कुल इस पर संज्ञान लूंगा और कार्य विभाजन कर वरिष्ठ अधिकारियों के निगरानी में विकास कार्यों का संचालन करवाया जाएगा जिससे विकास कार्यों में बहेतर गुडवत्ता लाया जा सके।

संतराम नेताम, विधायक केशकाल

# 36 गढ़िया स्वाभिमान की नई पहचान - लहलहाते खेत, खुशहाल किसान

कांग्रेस के 3 साल 3 बेमिसाल

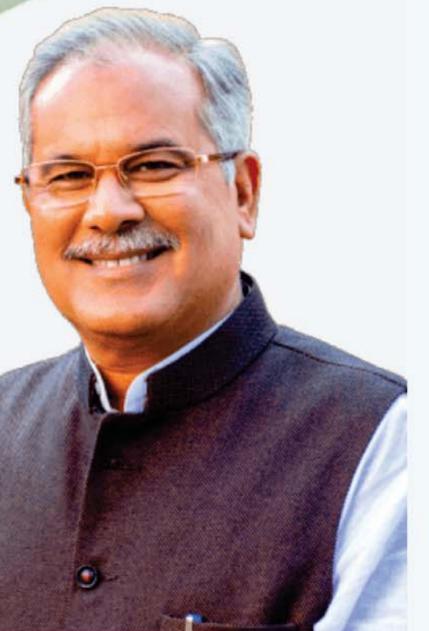


गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

36 गढ़िया स्वाभिमान की प्रतीक  
36 गढ़ की  
36 गढ़िया सरकार ने  
36 महीनों में रचे  
36 से अधिक कीर्तिमान

छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के परख जतन अउ पहिचान के विकास दुलार अउ सम्मान के

# हमर तीन बछर



छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम का विनम्र योगदान ...

छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा कक्षा पहली और दूसरी के लिए राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ी हल्की बैगानी बधेली सरगुजया जैसी 20 भाषा-बोली की द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों का वितरण कर देशभर में अनूठी पहल.

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की घोषणा के अनुक्रम में निगम के द्वारा कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी अध्यनरत स्कूली विद्यार्थियों को 'भारत का संविधान' लघु पुस्तिका का निशुल्क वितरण.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निगम द्वारा सामान्य ज्ञान पर आधारित पुस्तक 'प्रतियोगिता संसार' कक्षा 9 से 12 वीं तक के सभी शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क वितरण.

11 वीं 12 वीं कक्षा के लिए NCERT की पुस्तकें ऑनलाइन [www.tbc.cg.nic.in](http://www.tbc.cg.nic.in) पर उपलब्ध.

कक्षा 9 से 12 वीं तक के सभी शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को 'हम भारत के लोग' नामक लघु पुस्तिका का निशुल्क वितरण.

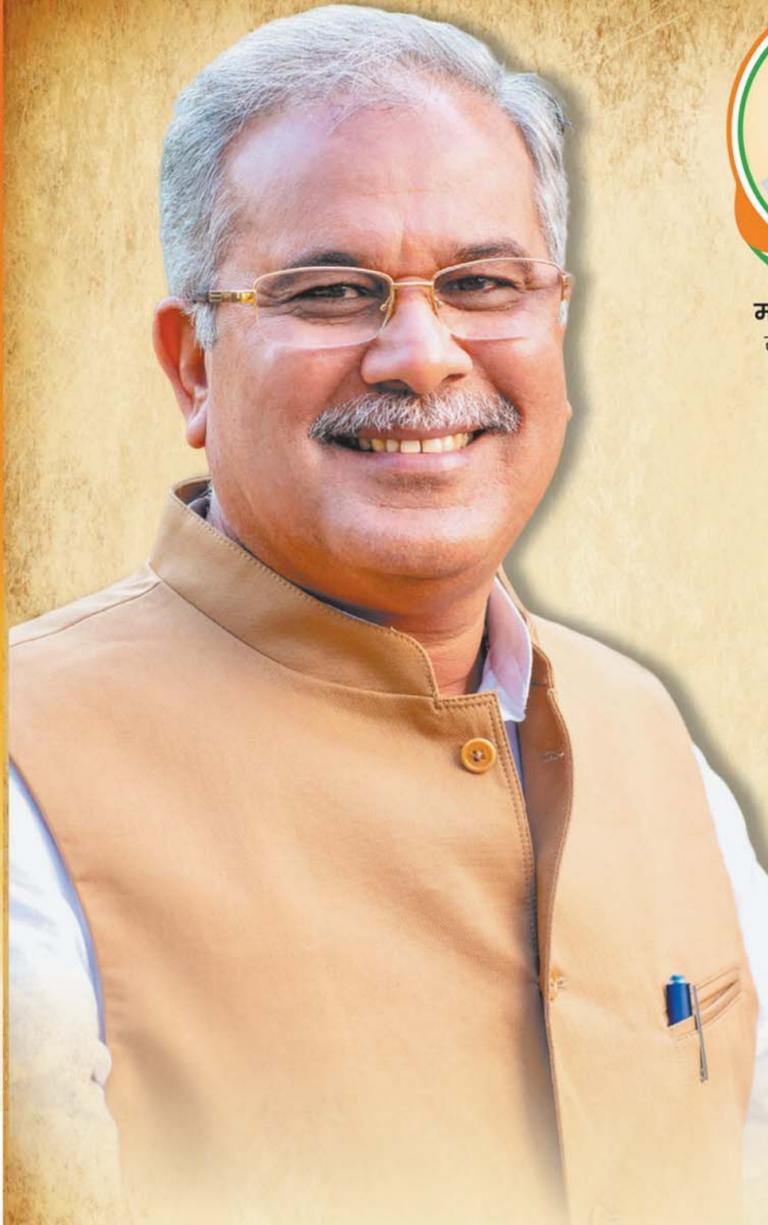
छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम मुख्यालय एवं संबंधित डिपो में प्राइवेट सिक्वोरिटी गार्ड्स के स्थान पर भूतपूर्व सैनिकों की गार्ड के पदों पर नियुक्ति. देश के सैन्य बलों का सम्मान.

कक्षा 3 से 10 वीं तक के सभी विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य एवं योगशिक्षा की (भाग 1,2 व 3) पुस्तकों का वितरण.

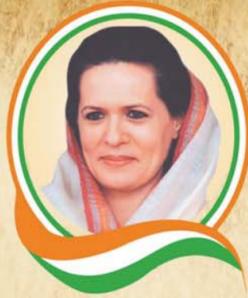
निविदाकारों के लिए छत्तीसगढ़ में स्थानीय जीएसटी पंजीयन अनिवार्य, ताकि जीएसटी के रूप में राशि राज्य शासन को प्राप्त हो.

शैलेश नितिन त्रिवेदी अध्यक्ष - पाठ्य पुस्तक निगम (छ.ग.)





**मान. श्री भूपेश बघेल जी**  
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



मान. सोनिया गांधी  
राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस



मान. राहुल गांधी  
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस



मान. पी.एल. पुनिया  
प्रदेश प्रभारी



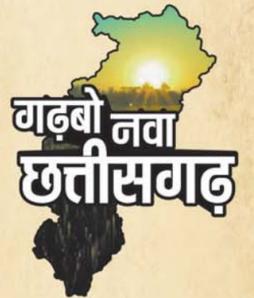
मान. शिवकुमार डहरिया  
श्रम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री



**मान. श्री गिरीश देवांगन जी**  
अध्यक्ष - खनिज विकास निगम  
छत्तीसगढ़ शासन



**मान. श्री रामगोपाल अग्रवाल जी**  
कोषाध्यक्ष - छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी  
अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम



## श्रम कल्याण के सरोकार - छत्तीसगढ़ सरकार

### श्रम कल्याण की उपलब्धियों भरे 3 वर्ष

- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजनांतर्गत **4312** श्रमिकों को **43.12** करोड़ से लाभान्वित
- भगिनी प्रसूति सहायता योजनांतर्गत **51982** श्रमिकों को **25.27** करोड़ से लाभान्वित

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन निःशुल्क

भगिनी प्रसूति सहायता योजनांतर्गत राशि अब एकमुश्त 10 हजार रु.

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजनांतर्गत अब 30 हजार के स्थान पर एक मुश्त 1 लाख रु. की सहायता

- नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना योजनांतर्गत **234470** श्रमिकों को **40.21** करोड़ से लाभान्वित
- मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत **5286** श्रमिकों को **4.38** करोड़ से लाभान्वित



**मान. सुशील सत्री अग्रवाल**  
अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ शासन सन्निर्माण एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल



# सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें युवा : शिशुपाल शोरी

पायनियर संवाददाता < कांकेर  
www.dailypioneer.com

पंडित विष्णुप्रसाद शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुर के खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसे संबोधित करते हुए संसदीय सचिव एवं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिशुपाल शोरी ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है।

युवा राष्ट्र की धारा को बदलने की क्षमता रखते हैं, जीवन के प्रत्येक गतिविधियों का नेतृत्व करने की उनमें क्षमता होती है, जो कुछ करने की तमन्ना रखते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। युवा वर्ग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और सक्रम लता प्राप्त कर अपने उपलब्धियों से अपना गांव, अपना जिला और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि युवाओं में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य शासन द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इससे युवाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, साथ ही सकारात्मक समाज के



निर्माण में भी मदद मिलेगी। शोरी ने युवा महोत्सव में शामिल सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उनके द्वारा गोविंदपुर के खेल मैदान में सौर ऊर्जा से संचालित दो हाई मास्क लगाने तथा शासकीय कार्यक्रमों के दौरान बालिकाओं के ठहरने के लिए भवन की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गई।

युवा महोत्सव के शुभारंभ समारोह को जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हेमनारायण गजबल्ला, जनपद पंचायत कांकेर के उपाध्यक्ष रोमनाथ जैन, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा तथा अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य ने भी संबोधित किया। युवा महोत्सव में जिले के सभी विकासखण्डों में आयोजित युवा महोत्सव के लगभग 700 विजेता युवा भाग ले रहे हैं।

## ग्राम धूमा में हृदयविदारक घटना मां ने दो मासूमों के साथ फांसी लगाकर दी जान, कारण अज्ञात

पायनियर संवाददाता < कुरुद  
www.dailypioneer.com

कुरुद थानांतर्गत आने वाली बिरेंद्वार चौकी क्षेत्र के ग्राम धूमा में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मां ने अपने दो मासूम बेटों के साथ घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की खबर मिलते ही कुरुद और बिरेंद्वार पुलिस मौके पर पहुंच गई है। खुदकुशी का कारण पता नहीं चल पाया है। जिन मासूम बेटों को मां ने दूध पिला कर बड़ा किया था आज ऐसी क्या वजह हो गई कि उन्हीं मासूम बेटों के साथ मां को खुदकुशी करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम धूमा में झरना साहू 26 वर्ष ने अपने बेटे सागर 6 वर्ष और अक्षय 4 वर्ष के साथ अपने कमरे में लगे जंगला के छड़ में दो साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बुधवार सुबह 6:30 से



8:00 के बीच बताई जा रही है। उस वक्त झरना का पति सब्जी बेचने गया हुआ था। सुबह जब तीनों को फांसी पर लटका देखा तो परिवार के लोग सकते में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ फांसी क्यों लगाई है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगिता आयोजन से उभरती प्रतिभाओं को पहचान मिलती है: योगेश तिवारी



पायनियर संवाददाता < बेमेतरा  
www.dailypioneer.com

ग्राम परपोड़ा में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में किसान नेता योगेश तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पुरस्कार बांटा। इस दौरान मुख्य

अतिथि ने उपस्थित जनो को संबोधित करते हुए कहा कि कबड्डी भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक है। कबड्डी को गांवों का खेल कहा जाता था, लेकिन अब कबड्डी विश्व के कई देशों में खेली जा रही है। देश में कबड्डी खेल को काफ़ी बढ़ावा मिला है। क्रिकेट की भांति अब कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की प्रतियोगिता से छुपी प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं, उन्हें मौका मिलने की जरूरत है। विजेता टीम को 10 हजार रुपए व उपविजेता टीम को 6 हजार रुपए नगद पुरस्कार दिया गया।

## स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 26 दिसम्बर को

वेबसाइट से अपलोड कर 17 दिसम्बर से प्राप्त किये जा सकेंगे प्रवेश पत्र

उत्तर बस्तर कांकेर। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग द्वारा कांकेर जिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों क्र।मासिस्ट ग्रेड-2, ड्रेसर ग्रेड-01 एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर भर्ती हेतु 26 दिसम्बर दिन रविवार को पूर्वाह्न 11.45 से दोपहर 02 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट www.issbbastar.cgstate.gov.in पर अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी 17

दिसम्बर से अपलोड कर प्रवेश पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा।

ऑनलाईन आवेदन करते समय प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर को एंटर कर अभ्यर्थी इंटरनेट से परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना होगा, जिससे उनके पहचान पत्र से पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केन्द्र में जाने हेतु अनुमति दिया जा सके। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र क्रोटो नहीं आता है तो अभ्यर्थी को अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज क्रोटो लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना होगा।

## जंगलबेडा ने जीता शिशुपाल कप कार्क बाल क्रिकेट प्रतियोगिता

पायनियर संवाददाता < सरायपाली  
www.dailypioneer.com

शिशुपाल पर्वत के तट पर स्थित मलदामाल में स्व निराकार भोंई के स्मृति में सरस्वती क्रिकेट समिति द्वारा आयोजित शिशुपाल कप अंडर पीसीएस कार्क गेंद क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जंगलबेडा और मलदामाल के मध्य खेला गया। जिसमें जंगलबेडा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट खोकर 110 रन बनाए इसके जबाब में मलदामाल ने 13 ओवर में 61 रन बनाकर आल आउट हो गई इस तरह जंगलबेडा 49 रन से फाइनल मैच जीत लिया। फाइनल मैच के मेन आक्र द मैच क्रिशन जंगलबेडा,



मेन आफ द सीरीज कमलेश जंगलबेडा, बेस्ट कीपर लिंगराज मलदामाल, बेस्ट कैच बबलू टेमरी, बेस्ट क्रील्डर रंजन मलदामाल, बेस्ट बल्लेबाज सुनील प्रधान मलदामाल, अनुशासित टीम भूतिया, बेस्ट गेंदबाज खिरोद मलदामाल। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राखी

गणेश चौहान पार्षद नगर पालिका परिषद सरायपाली अध्यक्षता धनुर्जय कश्यप अध्यक्ष पीसीएस विशिष्ट अतिथि अजय बाघ सरपंच ग्राम पंचायत मलदामाल, विनयरंजन भोंई, सुनील साहू सचिव पीसीएस, उमाशंकर धुव पीसीएस सदस्य रहे।

**माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के शानदार 3 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई**

- 1.40 लाख बच्चे कुपोषण मुक्त, 80 हजार महिलाएं एनीमिया मुक्त
- दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक योजना से 2 लाख महिलाओं का उपचार
- हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह, लाइवलीहुड कॉलेजों में कन्या छात्रावास

**विनीत - एक शुभचिंतक, महिला एवं बाल विकास विभाग**

**3 साल बेमिसाल**

**माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के शानदार 3 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई**

**एक शुभचिंतक बस्तर**

## संपादकीय

## अक्सर बंद स्कूल

## परेशान बच्चे

दिल्ली में स्कूलों के बच्चे परेशान हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर वे स्वास्थ्य मुद्दों को अपने तरीके से निपटाने के कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तोप का चारा बन गए हैं। राजधानी के स्कूल मार्च, 2020 में उस समय बंद हुए जब पूरे देश में कोरोना की पहली लहर के कारण लाकडाउन लगा। अगले बीस महीनों तक बच्चे घरों पर बंद दरवाजों के पीछे रहे। वे केवल अपने तक सीमित रहे, मित्रों से नहीं मिल सके तथा मैदानों में खेल नहीं सके। इस जबरन एकांतवास का उन पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ा। 1 नवंबर को अनेक स्कूलों में जूनियर कक्षाएँ खुलीं। कुछ निजी स्कूलों ने दीपावली के अंत तक स्कूल खोलना टाल दिया। बड़े बच्चों की कक्षाएँ सावधानी से सितंबर के प्रारंभ में खोली गईं। लेकिन बच्चों की मुसीबतों का यही अंत नहीं हुआ। 13 नवंबर को दिल्ली सरकार ने स्कूल फिर बंद करने के आदेश दे दिए। इसका कारण वैश्विक महामारी न होकर वायु प्रदूषण था। एक पखवाड़े बाद सरकार ने तय किया कि प्रदूषण का स्तर सहनीय हो गया है और स्कूलों को पुनः 29 नवंबर से खोलने का आदेश दिया, लेकिन वास्तव में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब था। 2 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल पुनः खोलने के लिए सरकार की खिंचाई की। इसके बाद सरकार ने फिर स्कूल फिर बंद कर दिए। अब माता-पिता स्कूलों के प्रति इस लापरवाही भरे दृष्टिकोण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से फौरन स्कूल खोलने का अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि प्रदूषण का स्तर घरों के बाहर और भीतर समान रूप से खराब है तथा सभी घरों में एयर प्यूरीफायर भी नहीं हैं।

सरकार और अदालतों को यह बात अवश्य समझनी चाहिए कि यदि स्कूल खोलने पर अनिश्चितता बनी रही जो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना होगा। बच्चों को महामारी-पूर्व के स्तर पर अपनी रूटीन लाने के लिए समय लगेगा। ऐसे में मनमाने ढंग से स्कूलों को बंद करने और खोलने से उन पर और दबाव पड़ेगा। दुनिया भर में इस बात के अध्ययन हो रहे हैं कि बच्चों पर स्कूल बंद करने का क्या प्रभाव पड़ा है। यूनेस्को, यूनीसेफ तथा विश्व बैंक ने एक वैश्विक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि 188 देशों में 1.6 बिलियन छात्र 20 महीनों तक स्कूलों से बाहर रहे। इस कालखंड में उनकी शिक्षा को भारी नुकसान हुआ है। आनलाइन शिक्षण के बावजूद जबरन एकांतवास के कारण 'भय पैदा हो रहा है कि सीखने में कमी के कारण उनमें असमानता और बढ़ेगी। यह असमानता विभिन्न देशों के बीच भी बढ़ेगी और इसे आने वाले वर्षों में ठीक करना कठिन होगा।' रिपोर्ट के अनुसार, उन देशों में दृष्टिकोण और खराब है जहां स्कूल जल्द से अधिक समय तक बंद रहे हैं। इस शोध से यह भी पता चला है कि सुदूर शिक्षा 'अक्सर अपने मानकों से पीछे रही' है। बच्चों के स्कूल जाना शुरू करने के बाद भारतीय माता-पिता का आंकलन है कि कक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें जीवन कौशल की शिक्षा पहले की तुलना में बेहतर है। अनेक स्कूलों ने पाया है कि स्कूल पुनः खुलने के बाद बच्चे खोई हुई अकादमिक उपलब्धियाँ जल्दी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जब तक कोई स्वास्थ्य आपातस्थिति न हो तब तक स्कूल बंद न किए जाएं। इसके बजाय ज्ञान प्राप्त करने में आई कमी दूर करने और खाई पाटने के खोजी प्रयास होने चाहिए।

## उर्वरक उद्योग की भूमिका पर सवाल

सरकार को यूरिया पर नियंत्रण हटा कर निर्माताओं को सब्सिडी देना बंद करना चाहिए। इसके बजाय सरकार सीधे किसानों को सब्सिडी दे सकती है।

उत्तम गुमा  
(लेखक नीति  
विश्लेषक हैं)



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर में कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, इंडियन आयल कॉर्पोरेशन व एफसीआईएल के संयुक्त सार्वजनिक उद्यम हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन की पुनर्जीवन योजना का उद्घाटन किया जहाँ 1.27 मिलियन नीम कोटिंग यूरिया का वार्षिक उत्पादन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने चार बातें कहीं। वर्तमान वर्ष में उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमत में भारी वृद्धि के बावजूद सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों को ज्यादा भुगतान न करना पड़े। 100 प्रतिशत नीम कोटिंग ने सुनिश्चित किया है कि यूरिया का गैर-कृषि औद्योगिक कार्यों में प्रयोग न हो सके। इस समय जारी चार अन्य पुनर्जीवन परियोजनाओं के साथ गोरखपुर परियोजना के क्रियान्वयन से यूरिया उत्पादन की वर्तमान 6 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन की क्षमता बढ़ कर 25 मिलियन टन हो जाएगी। इससे इसके आयात पर निर्भरता कम होगी तथा स्वायत्त हेल्थ कार्ड के प्रयोग से किसानों को यह जानने में सहायता मिली है कि मिट्टी को किस उर्वरक की आवश्यकता है और इस प्रकार उसके प्रयोग में असंतुलन रोकने में सहायता मिलेगी। इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि भारत में उर्वरक क्षेत्र में सब कुछ ठीक है। लेकिन हमें वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए। केन्द्र सरकार यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य को नीची दर पर बनाए रखती है, जिसका इसके उत्पादन और वितरण पर आने वाले खर्च से कोई संबंध नहीं है जो बहुत अधिक है। निर्माताओं को इसकी बिक्री व खर्च के बीच अंतर को भरपाई नई मूल्य योजना के आधार पर 'विशेष इकाई' के आधार पर की जाती है। इसके साथ ही उनको फैक्ट्री या बंदरगाह से खुदरा विक्रेता तक परिवहन के लिए समान भाड़ा नीति के



आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य-एमआरपी आज भी वही है जो 2002 में था और बाकी सभी गणनाओं को सब्सिडी बढ़ा कर उसमें जोड़ लिया जाता है।

फस्फेट व पोटाश-पीएंडके उर्वरकों के मामले में सरकार सभी निर्माताओं को पोषक आधार योजना के अंतर्गत प्रति पोषक आधार पर 'समान' सब्सिडी देती है। निर्माताओं को एमआरपी तय करने का अधिकार होता है, पर उनसे उम्मीद की जाती है कि इन्हें सब्सिडी की गणना शामिल होगी। उनको रेलवे स्टेशन तक परिवहन के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। अतीत में सरकार ने सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि लगातार बढ़ती मिलता है कि भारत में उर्वरक क्षेत्र में सब कुछ ठीक है। लेकिन हमें वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए। केन्द्र सरकार यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य को नीची दर पर बनाए रखती है, जिसका इसके उत्पादन और वितरण पर आने वाले खर्च से कोई संबंध नहीं है जो बहुत अधिक है। निर्माताओं को इसकी बिक्री व खर्च के बीच अंतर को भरपाई नई मूल्य योजना के आधार पर 'विशेष इकाई' के आधार पर की जाती है। इसके साथ ही उनको फैक्ट्री या बंदरगाह से खुदरा विक्रेता तक परिवहन के लिए समान भाड़ा नीति के

अप्रैल 2022 तक 5.93 डालर प्रति एमबीटीयू तथा अक्टूबर, 2022 से 7.65 डालर प्रति एमबीटीयू होने की आशा है। इसकी दो तिहाई सप्लाई यूरिया उद्योग को होती है। एक तिहाई आवश्यकता की पूर्ति करने वाली आयातित एलएनजी की कीमत अप्रैल में 5.5 डालर प्रति एमबीटीयू से बढ़ कर 14 डालर प्रति एमबीटीयू हो गई है और इसके अप्रैल 2022 के बाद 20 डालर प्रति एमबीटीयू होने की आशा है। जहां तक गैर-यूरिया क्षेत्र का सवाल है, इसकी कीमत में वृद्धि और ज्यादा है। आयातित डार्डामोनियम फस्फेट-डीएपी की कीमत 630 डालर प्रति टन है जो पिछले वर्ष की तुलना में 300 डालर अधिक है। डीएपी बनाने में लगने वाले कच्चे माल फस्फेरिक एसिड की कीमत लगभग 1000 डालर प्रति टन है जिसमें 375 डालर वृद्धि हुई है। डीएपी के एक और तत्व अमोनिया की कीमत 670 डालर प्रति टन है तथा इसमें 470 डालर की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार म्यूट आफपोटाश की कीमत 170 डालर प्रति टन हो गई है। जहां तक यूरिया का सवाल है, गैस मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि में 'स्वतः' अधिक सब्सिडी से शामिल हो जाती है जिससे एमआरपी अपरिवर्तित रहता है। पीएंडके उर्वरकों के मामले में भी मोदी सरकार ने सब्सिडी काफ़ी बढ़ाई है। डीएपी

पर यह सब्सिडी पिछले साल 10,000 रुपये प्रति टन थी जो इस साल बढ़ा कर 32,760 रुपये प्रति टन हो गई है। इस कारण एमआरपी पिछले साल की 24,000 रुपये प्रति टन की कीमत पर बनी हुई है। लेकिन इसका सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है।

2021-22 में केन्द्र ने सब्सिडी पर 58,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए, जबकि बजट आबंटन 80,000 करोड़ रुपये था। बहुत उदार राजकोषीय घाटे की नीति के कारण 1,38,000 करोड़ रुपये की यह भारी-भरकम सब्सिडी दी जा सकी जो जीडीपी का 6.8 प्रतिशत या 15,00,000 करोड़ रुपये है। लेकिन राजकोषीय घाटे में कमी लाने की स्थिति में यह रास्ता बंद हो जाएगा। 2016 में शत प्रतिशत नीम कोटिंग से यूरिया का अन्य कार्यों में प्रयोग बंद हुआ है जो लगभग 30 प्रतिशत था। 2015-16 में 30 मिलियन टन की कुल यूरिया बिक्री में यह 9 मिलियन टन था। इसका अर्थ है कि उस साल किसानों द्वारा यूरिया की मांग केवल 21 मिलियन टन थी। नीम कोटिंग से यूरिया का प्रयोग भी बेहतर हुआ है। इससे क्षमता में 20 प्रतिशत सुधार हुआ है, अतः किसान उतनी ही फसल पाने के लिए 16.8 मिलियन टन यूरिया प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन को 17 मिलियन

टन तक घटाया जा सकता है। यदि चीजें मोदी की योजनानुसार चलतीं तो 2020-21 में यूरिया का उपभोग 22 मिलियन टन होता, लेकिन वास्तव में इस साल 35 मिलियन टन उपयोग हुआ। इसका अर्थ है कि न यूरिया का दूसरे कार्यों में प्रयोग थमा और न उसकी क्षमता में कोई वृद्धि हुई। यदि वर्तमान समय में वादा पूरा हो तो किसानों को 20 मिलियन टन से अधिक यूरिया की जरूरत नहीं होगी। यह सप्लाई प्रबंधन में भारी कमी की ओर इशारा करता है। वर्तमान 25 मिलियन टन के उत्पादन को देखते हुए भारत को एक टन आयात की भी जरूरत नहीं होगी चाहिए, जबकि 2020-21 में 10 मिलियन टन आयात हुआ। यदि चीजें सही दिशा में चलतीं तो देश को पांच पुनर्जीवन परियोजनाओं की आवश्यकता न होती। जहां तक एसएचसी का सवाल है, नीतिगत समर्थन से इसकी क्षमता में विस्तार हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ वर्तमान समय में डीएपी की कीमत 24,000 रुपये प्रति टन है जो 5,360 रुपये प्रति टन यूरिया की तुलना में 4.5 गुना अधिक है। किसान को एनपीके प्रयोग में संतुलन बनाने के लिए यूरिया का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में यदि एसएचसी किसानों को ज्यादा डीएपी प्रयोग की सलाह देता है तो यह किसान के लिए महंगा सौदा होगा।

उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए यह पूरी तरह स्पष्ट है कि उर्वरक क्षेत्र में सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी सरकार को नीतिगत परिवर्तन करते हुए यूरिया पर नियंत्रण हटा कर निर्माताओं को सब्सिडी देना बंद करना चाहिए। इसके बजाय सरकार सीधे किसानों को सब्सिडी दे सकती है। इससे किसानों की स्थिति मजबूत होगी और वे उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी का प्रयोग मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कर सकेंगे तथा उर्वरक प्रयोग में असंतुलन दूर होगा। बाजार में किसी सब्सिडी वाले उर्वरक उत्पाद का न मिलना सुनिश्चित होने के बाद नई व्यवस्था यूरिया का अन्य कार्यों में प्रयोग हतोत्साहित करेगी। यूरिया की मांग वास्तविक स्तर पर आने से सप्लाई बढ़ाने पर आने वाला दबाव भी कम होगा। इससे सब्सिडी में भी भारी कमी आएगी।

## गांव गरीब और किसान की सरकार

कांग्रेस की सरकार ने गांव गरीब और किसान के चौमुखी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है सरकार का मानना है कि शहर में विकास की चमक गांव की पगडि़यों से होकर पहुंचती है।

घनश्याम राजू तिवारी



कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चमत्कारी नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ 3 वर्ष पूरे करने में सफलता पाई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने गांव गरीब और किसान के दर्द को महसूस किया है जिसका निवारण करने को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है जिसके फलस्वरूप आज गांव गरीब और किसान उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है प्रदेश में चारों ओर खुशहाली की बयार बह रही है। गोबर अब शायद लोग गोबर का उल्हाना देना छोड़ दें, कारण की गोबर अब गोबर-घन साबित हो रहा है। प्रदेश का आमजन युवा माताएं बहने अब गोबर बेच कर अपने सपने साकार कर रहे हैं युवा गोबर बेचकर मोबाइल ले रहे हैं जिसके माध्यम से शिक्षा व कला में पारंगत हो रहे हैं माताएं बहने गोबर बेचकर आभूषण व अन्य जरूरत का सामान खरीद रहे हैं



इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुखद पहलू यह है कि गोवंश गोधन सुरक्षित हो रहा है जिस भाजपा ने गाय के नाम पर सारी जिंदगी राजनीति की है उन्हें उन्हीं की भाषा में गोबर से जवाब देने का करिश्माई करिश्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठीक कर सकते हैं उनके विकास परक सोच की सीमाएं अनंत है। कांग्रेस की

सरकार ने गांव गरीब और किसान के चौमुखी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है सरकार का मानना है कि शहर में विकास की चमक गांव की पगडि़यों से होकर पहुंचती है किसान की खुशहाली देश की समृद्धि शांति की पहचान है। पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान जागा है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया धनरा

देश में गुंजा है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज त्योहारों का परंपराओं को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए छत्तीसगढ़ के अस्मिता को सहेजने वह सवारने का सार्थक प्रयास किया है। कांग्रेस भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हुए उनके

जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, आज किसानों के खाते में करोड़ों रुपए बिना किसी मध्यस्ता के सीधे तौर पर भुगतान हो रहे हैं। भाजपा के कुशासन में किसान होना दर्द का अनुभव देता था परंतु आज कांग्रेस के सुशासन में किसान होना गौरव की अनुभूति प्रदान करता है। इसी तरह इन 3 वर्षों में चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में उत्तरोत्तर प्रगति की है नए मेडिकल कॉलेज की मान्यता दी गई है ताकि छात्र बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। जिससे प्रदेश व समाज लाभान्वित हो सके इसी क्रम में जेनेरिक मेडिकल स्पॉट खोले गए हैं जिनसे सभी दवाइयों आधे दामों पर खरीदी जा सके। नगरों व शहरों की साफसफाई व स्वच्छता पर केंद्र द्वारा सम्मान मिलना सरकार की उपलब्धियों का उद्घोषक है। देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश का होना समस्त छत्तीसगढ़वासियों के लिए गौरव की बात है। ऐसी ही अनगिनत उपलब्धियां हैं जो सरकार को अंतरित करती हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस भूपेश सरकार का विकास परक नीतियों के कारण ही आज छत्तीसगढ़ व छत्तीसगढ़वासियों की धमक विश्व पटल पर गुंज रही है।

लेखक

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है।

## फरमाया



हम सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने नहीं दिया जाता है। यह लोकतंत्र की हत्या है।

- राहुल गांधी  
कांग्रेस नेता



अमेरिका ने अफगानिस्तान में गलतियों की और पाकिस्तान को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है।

- इमरान खान  
पाक वज़ीर आजम



काशी में इतिहास का एक सुनहरा स्वरूप बनाया गया है जो धर्म और आस्था के इस धाम को रोशन करता रहेगा।

- योगी आदित्यनाथ  
यूपी के मुख्यमंत्री

## आप की बात



इस कॉलम में अपने विचार या प्रतिक्रिया भेजने के लिए हमारे ई-मेल से pioneer.editorial@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

www.dailypioneer.com

## यादगार और चुनौतियों का दिन

13 सितंबर 2021 भारत के लिये यादगार और चुनौती देता दिन है। आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था। उस हमले को नाकाम बनाने के लिये वीर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आतंकियों को ढेर कर दिया। 20 वीं बरसी पर कश्मीर में सशस्त्र पुलिस बलों की बस पर आतंकियों ने श्रीनगर के पन्था चौक पर गोलीबारी कर हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी शहीद और 12 अन्य जख्मी हो गए। उत्तरी कश्मीर में एक नेता की सुरक्षा में तेनात पुलिस कर्मी अपने साथी के साथ दो अस्पष्ट राइफलें और कारतूसों की मैगजिन लेकर फरार हो गया। पूर्व में भी तमाम पुलिस कर्मी आतंकी संगठनों में शामिल हो गए। 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगी ऐसा दावा सरकार करती है। लेकिन आतंकियों के पास हथियार और गोलाबारी का सामान कहां से आता है। इनके मददगार और संचालकों के सफाया करने की ओर अभियान अबतक नहीं चलाया गया। कश्मीर में आतंकी घटनाएं आतंरिक सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। आज तकनीकी युग में देश की पलपल खबर भेजने वाले आस्तीन के सांघो की भरमार हो गई है। उदारवादी सरकार आतंरिक सुरक्षा को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दे रही है।

- कुलदीप मोहन त्रिवेदी, जरांग

## आर्थिक असमानताएं

एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी हिस्सा देश के सर्वाधिक अमीर 10 फीसदी लोगों और उसमें भी 22 फीसदी हिस्सा सुपर अमीरों के हिस्से जा रहा है, जबकि आबादी के निचले पायदान पर बैठे 50 फीसदी भारतीय राष्ट्रीय आय के सिर्फ 13 फीसदी में किसी तरह गुजारा चलाने के लिए मजबूर हैं। देश के 40 फीसदी मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की भी स्थिति अच्छी नहीं है, जो कुल राष्ट्रीय आय के सिर्फ 30 फीसदी में गुजर-बसर कर रहे हैं। यही नहीं, संपत्ति में हिस्सेदारी की स्थिति और बदतर है, जो आर्थिक गैर-बराबरी को और भी तीखा, गहरा और स्थायी बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल संपत्ति में लगभग दो तिहाई यानी 65 फीसदी हिस्से पर देश के शीर्ष 10 फीसदी अमीरों का कब्जा है, जबकि निचले 50 फीसदी भारतीयों के हिस्से में सिर्फ 6 फीसदी संपत्ति आती है। इसमें भी टॉप एक फीसदी सुपर अमीर कुल संपत्ति के 33 फीसदी पर काबिज हैं, जबकि देश की आबादी के 40 फीसदी मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 30 फीसदी हिस्सा है। सौ अर्थशास्त्रियों की रपट में भारत के संबंध में जो आंकड़े दिए गए हैं वे चौंकाने वाले हैं।

- सुभाष बुड्ढावनवाला, रतलाम

## चिंताजनक सच

इसे सौभाग्य कहा जाय या दुर्भाग्य? हमें गौरवान्वित होना चाहिए की अयमानित? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को जानकारी दी के सिर्फ इस साल, यानी 20 सितंबर 2021 तक, 1,11,287 भारतीयों ने, अपनी नागरिकता को त्याग दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 7 वर्षों के दौरान, साढ़े सात लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को अलविदा कह दिया। किसी अन्य देश में इतनी बड़ी संख्या में किसी ने ऐसा नहीं किया। हां गृहयुद्ध एवं भुखमरी के कारण लाखों लोग अन्य देशों में, खानाबदोश जीवन जीने को विवश जरूर हुए। मगर इच्छा से किसी ने अपना मुल्क को नहीं त्यागा। अगर हम अमेरिकियों का नागरिकता त्यागना का रिकॉर्ड को देखें तो हमारी तुलना में नगण्य सा है। 2019 में सिर्फ 2072 एवं 2020 में केवल 5800 अमेरिकियों ने नागरिकता का त्याग किया था। शायद भारत में अवसरों, नौकरियों एवं सुख सुविधाओं में सख्त कमी होती जा रही है। यहां डॉक्टर्स, इंजीनियरों, उच्च कोटि के प्रबंधकों एवं अन्य पेशेवरों के लिए, कोई काम ही नहीं है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर



# कलेक्टर के आदेश को किया दरकिनार पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही जारी

चंद्रपुर महानदी पुल में मरम्मत कार्य के लिए 15 दिसम्बर से बड़े वाहनों का आवागमन पर लगा था रोक



जिले के कलेक्टर के आदेश का कोई परवाह नहीं होते दिख रहा है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले के संवेदनशील कलेक्टर श्री जितेंद्र शुक्ला द्वारा चंद्रपुर महानदी पुल में मरम्मत कार्य होने के कारण 15 दिसंबर से आवागमन को जो भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मगर देखने को मिल रहा है कि नेशनल हाइवे के अधिकारियों की तैयारी आधी अधूरी देखी जा रही है। जिससे कि उनके द्वारा कलेक्टर द्वारा किये गए आदेश को दरकिनार करते हुए अपने मन से तिथि को बढ़ा ले

15 दिसंबर से भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश की कॉपी निकाल दी है। जिस पर सभी पत्रकारों ने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत प्रचार प्रसार कर दिया गया था। जिस पर कई कंपनियों जो इस रोड में काम करती है उन संस्थाओं ने अपने कार्यों को बंद करके जो इस चंद्रपुर महानदी पुल से होते हुए अपना कार्य करते हैं। इस चंद्रपुर महानदी पुल में भारी वाहनों का कार्य करते हैं वे अपनी सारी वाहनों को दूसरे जगह भेज कर अपना कार्य करने लगे हैं

तथा जो स्थानीय कर्मचारी उनके संस्थान में है उनको इस पुल की मरमत होने तक छुट्टी दे दी गई है। क्योंकि यह पुल 15 दिसंबर से बंद होने के उपरांत उनको जो रास्ता मिलेगा उसमें उनके मार्ग में बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ता था। इसलिए उनके द्वारा चंद्रपुर महानदी पुल में मरम्मत होने तक अपना कार्य 15 दिसंबर से बंद कर दिया गया था। क्योंकि 15 दिसंबर का आदेश जिले के कलेक्टर साहब द्वारा निकाला गया था। और नेशनल हाइवे वाले कलेक्टर के आदेश को दरकिनार करते हुए अपना आदेश निकालते हुए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। आप देखने और सोचने वाली बात है कि आखिर नेशनल हाइवे रोड की अधिकारियों को कलेक्टर के आदेश की तिथि को क्यों बढ़ाना पड़ा? और जब तिथि बढ़ाना ही था तो जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई।

## धान खरीदी में अनियमितता, भोथिया खरीदी केन्द्र प्रभारी को कारण बताओ सूचना जारी

पायनियर संवाददाता < सक्ती  
www.dailypioneer.com

किया गया। निरीक्षण में तैल किये गए बोरी से धान चोरी कर निकलना, खरीदे गये धान का स्टैक नहीं लगाना, खरीदे गये धान का वजन अधिक/कम होना और धान में नमी की मात्रा अधिक पाया गया, उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ शासन के धान खरीदी नीति का उल्लंघन है। इस संबंध में स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर धान खरीदी केन्द्र प्रभारी श्री अशोक कुमार चन्द्रा को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने कहा गया है, स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में सहकारी सेवा नियम के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने पर जांजगीर चांपा जिले के भोथिया धान उपार्जन केन्द्र के प्रभारी अशोक कुमार चन्द्रा को जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने कारण बताओ सूचना जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है, नोडल अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार शनिवार 11 दिसंबर को जाँचकर्ता अधिकारी बारादार शाखा के स.वि.अ. सुशील कुमार सूर्यवंशी एवं पर्यवेक्षक रोहित कुमार राठौर द्वारा भोथिया उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण

**इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उद्यम - जिंजी रेल)  
सीआइएन नं. L74899DL999GO101707

आईआरसीटीसी निम्नलिखित के लिए ई-बोली/ई-आरएफपी आमंत्रित करता है:-

- 1) इट्टीगेटेड रेलवे हेल्थिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम-139 के लिए मेनेज्ड सर्विस पार्टनर के चयन के लिए। पहली प्री-बिड मीटिंग (वीसी): 20.12.2021 को 12:30 बजे, दूसरी प्री-बिड मीटिंग 06.01.2022 को 12:30 बजे।  
जमा करने की अंतिम तिथि: 24.01.2022।
- 2) बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 'रेल नीर' पैकेज्ड पेयजल संचयन के लिए ऑपरेटर के चयन के लिए। प्री-बिड मीटिंग: 28.12.2021 को 15:00 बजे आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में।  
जमा करने की अंतिम तिथि: 18.01.2022 15:00 बजे तक।
- 3) आईआरसीटीसी/उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय रेलवे पर एए और ए के स्टेशनों के तहत जलपान यंत्रों और जन आहार में/के माध्यम से खानपान सेवाओं के संचालन, रखरखाव और प्राधान्य के लिए।  
निविदा उपलब्धता: 20.12.2021, जमा करने की अंतिम तिथि: 10.01.2022 15:00 बजे तक।
- 4) आईआरसीटीसी/उत्तरी क्षेत्र के तहत भारतीय रेलवे के बी. सी और डी श्रेणी के स्टेशनों पर फास्ट फूड इकाइयों की स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए।  
निविदा उपलब्धता: 20.12.2021, जमा करने की अंतिम तिथि: 11.01.2022 को 15:00 बजे तक।
- 5) आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए वेटवॉट समाधान प्रदाता के चयन के लिए प्रतियोगिताओं से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।  
जमा करने की अंतिम तिथि: 23.01.2022 15:00 बजे तक।

निविदा प्रस्तावों के लिए वेबसाइट [www.irctc.com](http://www.irctc.com) (क्र.1 से 5 के लिए), [www.tenderwizard.com/IRCTC](http://www.tenderwizard.com/IRCTC) (क्र.1 से 5 के लिए) तथा [eprocure.gov.in/cppp](http://eprocure.gov.in/cppp) (क्र. 3 एवं 4 के लिए) पर देखें। उपरोक्त निविदा दस्तावेजों को ऑनलाइन डाउनलोड करना और जमा करना केवल [www.tenderwizard.com/IRCTC](http://www.tenderwizard.com/IRCTC) वेबसाइट पर ही किया जा सकता है।  
सुदृष्टि/परिशिष्ट केवल [www.irctc.com](http://www.irctc.com) तथा [www.tenderwizard.com/IRCTC](http://www.tenderwizard.com/IRCTC) पर प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यालय पता: समूह महाप्रबंधक (पी एंड टी), आईआरसीटीसी लिमिटेड 11वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बी-148, बाराकम्पा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001, टेली: 011-23311263-64

समर्थन मूल्य पर क्रय योग्य वनोपज 7 से बढ़कर अब 52 लाख उत्पादन को भी अब कृषि का दर्जा कोदो, कुटकी, रागी, का भी क्रय

आदिवासी और वन आश्रित परिवारों की अतिरिक्त वार्षिक आय 502 करोड़ रूपए



## मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना

- गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती फलदार वृक्ष, बांस, अन्य लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण किया जाएगा तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जाएंगे।
- जिस भूमि पर वन अधिकार पत्र दिये गये हैं, उस भूमि पर भी हितग्राहियों की सहमति से इमारती, फलदार, बांस, लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र में पूर्व से खड़े वृक्ष एवं स्वयं रोपित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन हेतु अनुमति के प्रावधानों को और अधिक सरल तथा सुगम बनाया जाएगा।
- राजस्व विभाग नियमों में इस प्रकार संशोधन करेगा, जिससे नागरिकों को वृक्ष लगाने एवं काटने हेतु राजस्व एवं वन विभाग को सूचना देने मात्र की आवश्यकता हो। स्वयं द्वारा रोपित पौधों को काटने हेतु किसी विभाग के अधिकारी से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित हो सकें।
- ग्राम पंचायतों तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित संस्था को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इससे भविष्य में इन संस्थाओं की आय में वृद्धि हो सकेगी।
- जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

**3 साल बेमिसाल**

**3 साल बेमिसाल**

# बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारी सशक्तीकरण के नए कदम



- हरेली, तीजा, भक्तमाता कर्मा जयंती, छठपूजा, विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा कमेटीयों में भागीदारी
- जिला खनिज न्यास संस्थान में महिलाओं की भागीदारी
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि में वृद्धि
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं व स्वच्छता दीदियों के मानदेय वृद्धि

- महिला स्व-सहायता समूहों के बरसों से लवित ऋण माफ
- छत्तीसगढ़ महिला कोष के बजट में 5 गुना वृद्धि
- कोष से महिला समूहों को मिलने वाली ऋण राशि दो गुनी
- गोधन न्याय योजना में 45 प्रतिशत भागीदारी
- वनोपज संग्रहण में स्व-सहायता समूहों की भागीदारी



- 1.40 लाख बच्चे कुपोषण मुक्त, 80 हजार महिलाएं एनीमिया मुक्त
- दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक योजना से 2 लाख महिलाओं का उपचार

- हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह
- लाइवलीहुड कॉलेजों में कन्या छात्रावास

- 9 जिला मुख्यालयों में नए महिला महाविद्यालय शुरू
- स्नातकोत्तर तक नि:शुल्क शिक्षा
- कॉलेजों में बालिकाओं की प्रवेश संख्या बालकों से ज्यादा

**एक शुभचिंतक**



**खैरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चुनावी सभा में उमड़ी भीड़**

**सीएम की हुंकार, दो साल पहले की जीत फिर दोहराने का दावा, रोड शो भी किया**

पायनियर संवाददाता राजनंदगांव  
www.dailypioneer.com

निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को खैरागढ़ में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की जीत का विश्वास जताते हुए सीएम ने हुंकार भरते हुए बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा 2 साल पहले हमने प्रदेश भर में निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराया था वो फिर दोहराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश सरकार की योजनाओं और उससे आमजन को मिल रहे फायदों की बात की।

कांग्रेसियों ने सीएम की आमद पर पूरी ताकत झोंक दी और उनका स्वागत किया। जिले भर के नेता इस दौरान खैरागढ़ पहुंचे थे। खबरें हैं कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस दौरान संगठन के भीतर चल रही उठापटक और कुछ अन्य के खिलाफ शिकायतें भी सीएम तक पहुंचाई हैं। इनमें से कुछ की शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लगभग एक घंटे देर से पहुंचे सीएम के साथ मंत्रीमंडल के रविंद्र चौबे, रुद्र गुरु, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे।



खैरागढ़ में आमसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के नीति

जनता से परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निकायों में

जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ की जनता से शहर के सतत विकास के लिए

कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।

इधर मुख्यमंत्री ने मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में केंद्र पर एक बार फिर हमला बोलते कहा कि 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को मोदी सरकार ने रोक दिया है। जिसका कई योजनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बनाने की मांग पर खैरागढ़ की जनता के साथ है। खैरागढ़ के विषय पर स्थानीय जनभावनाओं का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समूचे राज्य में कांग्रेस के पक्ष में लहर है।

**अचानक पहुंचे धान खरीदी केंद्र**

खैरागढ़ में रोड शो और चुनावी सभा के बीच अचानक ही मुख्यमंत्री खैरागढ़ क्षेत्र के ही जालबांधा धान खरीदी केंद्र पहुंच गए। यहाँ उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता को लेकर भी बात की। गौरतलब है कि एक दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी में किसानों से 25 प्रतिशत बारदाने 25 रुपए की दर से लेने के आदेश जारी हुए थे। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि किसानों को सोसायटियों से 75 प्रतिशत से कई कम बारदाने दिए जा रहे हैं।

इस चुनाव में भाजपा मैदान में नहीं है। इससे पहले सीएम बघेल ने नगर में रोड शो किया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी।

आम लोगों ने भी मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान उनका स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने नगर की जनता का अभिवादन स्वीकार किया।

**मुद्दों से दूर प्रत्याशियों की छवि पर ही लगेगी मुहर कई तरह की चर्चाओं के बीच आंकलन कर रहे मतदाता**

- भाजपा के पास नया चेहरा इसलिए कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं
- कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पूरी सत्ता ने ताकत झोंकी

पायनियर संवाददाता राजनंदगांव  
www.dailypioneer.com

शहर में उपचुनाव की सरगमी बड़ गई है। वार्ड क्र. 17 में पार्षद पद हेतु हो रहे उपचुनाव में दोनों ही दलों के पास कोई खास मुद्दे नहीं हैं ऐसे में मतदाता दोनों ही प्रत्याशियों की छवि का आंकलन कर अपना मन बना रहे हैं। इस स्थिति में भाजपा को नए चेहरे का फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका यह चुनाव और भी मुश्किल हो सकता है। इसका कारण उनकी प्रत्याशी को लेकर

जारी कई तरह की चर्चाएं हैं। दरअसल, कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन के परिवार से जुड़े कुछ विवादों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें चल रही हैं। वार्ड क्र. 17 तुलसीपुर में 30 सालों से भाजपा लगातार अपनी जीत का परचम लहरा रही है। निकाय चुनाव में यहां से पूर्व महापौर शोभा सोनी ने भाजपा की ओर से जीत दर्ज की थी। वे महापौर पद की भी दावेदार थीं लेकिन भाजपा को बहुमत हासिल न होने के चलते ऐसा नहीं हो सका। भाजपा पार्षद दल ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना था। इसी दौरान कोविड की पहली लहर में वे संक्रमित हो गईं और रायपुर के एम्स में उनका निधन हो गया।

श्रीमती सोनी के निधन के बाद अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा जिलाअध्यक्ष मधुसूदन यादव भी यहां से पार्षद रह चुके हैं।



**भाजपा को जीत का भरोसा**  
नया चेहरा होने के चलते सरिता सिन्हा को पीछे धकेलने कांग्रेस के पास कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं। स्व. शोभा सोनी के कार्यकाल में भी भाजपा को लेकर किसी तरह की शिकायत यहां नहीं रही। स्व. श्रीमती सोनी भी यहां काफी बड़े अंतर से जीतकर आई थीं। भाजपा को दोबारा भी ऐसी ही जीत का भरोसा है। वार्ड में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वरिष्ठ नेताओं के अलावा वार्ड प्रभारी राजेंद्र गोलख, नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु, पार्षद पारस वर्मा, भाजयुमो पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी यहां कमान संभाले हुए हैं।



**कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है**  
कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन लंबे समय से वार्ड में चुनाव को लेकर सक्रिय रहीं हैं। वे चुनावों की घोषणा से पहले ही घर-घर पहुंच कर मेल-मुलाकात करती रहीं हैं। लेकिन उनके परिवार से जुड़े कुछ विवादों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि कांग्रेसी खेमा श्रीमती देवांगन की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। खुद महापौर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा और कांग्रेस भी कांग्रेसी नेता यहां रोजाना पहुंच रहे हैं।



तो दूसरी ओर भाजपा ने जमीनी कार्यकर्ता की पत्नी सरिता सिन्हा को नए चेहरे के तौर पर मैदान पर उतारा है।

**मतदान एवं मतगणना के दिन बंद रहेंगी मदिरा दुकानें**

नगर पालिका आम एवं उप निर्वाचन 2021 को संपन्न कराने के लिए मतदान तथा मतगणना के दिन शराब दुकानें, होटल बार, क्लब आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। नगर पालिका आम एवं उप निर्वाचन का चुनाव 20 दिसम्बर को एवं 23 दिसम्बर को मतों की गणना की जाएगी। मतदान तिथि 20 दिसम्बर से 48 घण्टे पहले अर्थात् 18 दिसम्बर को शाम 5 बजे से 20 दिसम्बर को मतदान समाप्त तक देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसी प्रकार मतगणना के दिन 23 दिसम्बर को संपूर्ण दिवस देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में शुष्क दिवस के दौरान अवैध मदिरा, धारण, परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

**मतदान के लिए मिलेगा अवकाश**

नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के पार्षद पदों के आम एवं उप निर्वाचन 2021 के लिए नियत 20 दिसम्बर को मतदान होगा। कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, कारोबारों, व्यवसायों, औद्योगिक उपकरणों में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए मतदान दिवस 20 दिसम्बर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है।

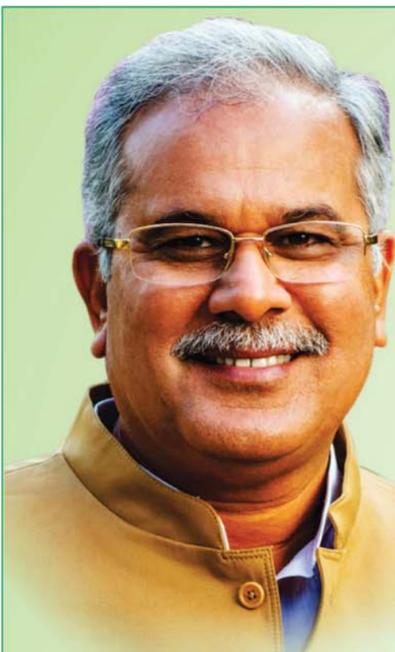
**ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 8 से 14 दिसम्बर तक मनाया गया**



डोंगरगढ़। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल शाखा डोंगरगढ़ में 8 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक रेलवे के द्वारा विद्युत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया। रेली के माध्यम से कालोनी में भ्रमण कर लोगों से विद्युत की खपत को कम करने और जरूरत होने पर ही उसका उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया है। सभी से अपील की गई। वहीं इस अभियान में रेलवे के पुनत राम गंगुबर वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर विद्युत विभाग एवं दिनेश साहू, रूपेश साहू, धर्मेन्द्र महाराणा, मनोज, संत राम, विश्वनाथ नारायण, इंदिरा, उषा, गिरजा, राजेश भारद्वाज सहित इस जागरूक अभियान में आज उपस्थित थे।

**18 को मटन मार्केट बंद**

राजनंदगांव। राज्य शासन के निर्देशानुसार गुरुवासी दास जयती के उपलक्ष्य में दिनांक 18 दिसम्बर दिन शनिवार को नगर निगम सीमाक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं मटन मार्केट पूर्णरूपेण बंद रहेंगे। महापौर हेमा सुदेश देशमुख एवं नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चटुवेदी ने स्वास्थ्य विभाग को उक्त दिवस पर पशुवध एवं विक्रय कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित सुनिश्चित करने कहा है।




मान. मुख्यमंत्री

**श्री भूपेश बघेल जी एवं अकबर भाई**

के शानदार **3 साल** पूरे होने पर

**हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं**

36 गढ़ के उड़ान का 36 महिना

**धान का सर्वाधिक मूल्य देने की देशभर में हुई सराहना**

**गढ़बो नवा छत्तीसगढ़**



**गोरेलाल चंद्रवंशी**  
सचिव सरपंच संघ एवं मीडिया प्रभारी  
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बोड़ला



**पीताम्बर वर्मा**  
अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बोड़ला



# निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का धरना प्रदर्शन, आज भी बैंक रहेंगे बंद

पायनियर संवाददाता < बिलासपुर  
www.dailypioneer.com

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिवर्स के आह्वान पर चार अधिकारियों व पांच कर्मचारियों की यूनिवर्स से सम्बंध समस्त सदस्य आज सुबह 8 बजे से 48 घण्टों की हड़ताल पर चले गए हैं। प्रातः 10 बजे केनरा बैंक, मंगला शाखा, 36 मॉल के सामने सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के प्रस्तावित विधेयक के विरोध में श्री शरद बघेल व सौरभ त्रिपाठी के नेतृत्व में हड़ताल, धरना व जंगी प्रदर्शन हुआ। 11 बजे स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए ट्रेड यूनियन कौशल के महासचिव कामरेड राजेश शर्मा ने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा वापिस लिए गए कृषि कानूनों को लाने से पहले सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का सपना दिखाया गया और उसके बाद में तीन कृषि कानून लाये गए। किसानों को समझ में आ गया कि इन कानूनों से उनका क्या फायदा या नुकसान होने वाला है और वो दिल्ली के बौडों पर आकर जम गए और जब तक कृषि कानून वापिस नहीं लिए गए तब तक मजबूती से इसके विरोध में उठे रहे।

एटक के कामरेड पवन शर्मा ने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा एक कार्यक्रम करके डिपॉजिट इंश्योरेंस पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित करके देश के लोगों को ये बताया गया कि आपके बैंकों में जमा पंजी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि 5 लाख तक की राशि का बीमा है। इसी के साथ शीतकालीन सत्र में बिललाने की तैयारी की गई है ताकि सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का रास्ता साफ किया जा सके। डिपॉजिट इंश्योरेंस के कार्यक्रम के द्वारा देश के लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि बैंकों के निजीकरण के बाद उनकी जमा राशि सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ बैंक एम्प्लाइज एशोसिएशन के सहायक महासचिव द्वय कामरेड मनोज मिरी व कामरेड प्रल्हाद अग्रवाल ने बताया कि देश के नागरिकों को क्रोनोर्लाजी समझने की जरूरत है -- -किसानों की आय दुगुनी होना- और +5 लाख तक की बैंकों में जमा राशि का बीमा होना। अशोक ठाकुर व शैलेन्द्र गोवर्धन ने बताया कि आजादी से पहले 300 से ज्यादा निजी बैंकों के डूबने और दीवालिया होने के मामले हैं और उनके डूबने से उन बैंकों में जिन ग्राहकों के पैसे



जमा थे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था और हाल ही में पीएमसी बैंक और यश बैंक दो ताजा उदाहरण हैं जिनके ग्राहकों ने किन परिस्थितियों का सामना किया था। राजेश रावत व श्रवण मिश्रा ने बताया कि इस देश के उन नागरिकों को सोचना होगा जिनकी जिंदगी भर की कमाई इन सरकारी बैंकों में जमा है जिनको प्राइवेट करने पर विचार किया जा रहा है तथा दूसरी सरकारी बैंकों

के ग्राहकों को अपनी बारी का इंतजार किए बिना सोचना चाहिए कि आज किसी दूसरे का नंबर है तो कल हमारा होगा। केनरा बैंक के शरद बघेल व सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि बैंकों के निजीकरण करने के सरकार के फैसले के विरोध में अभी बैंक में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और इसी संबंध में दिनांक 16 एवं 17 दिसंबर को दो दिवसीय हड़ताल जारी है। क्योंकि निजीकरण, बैंकों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के हितों के खिलाफ तो है ही साथ में इस देश के लोग जो इन बैंकों के ग्राहक हैं उनके हितों के खिलाफ भी हैं। जितेंद्र शुक्ला व दीपक साहू ने बताया कि हड़ताल इस देश की सरकारी संपत्ति बचाने के लिए है और इस देश की जनता के लिए है। इस देश के सभी नागरिकों को इस मुद्दे से जुड़कर इसे सफल बनाना चाहिए। अमृता सिंह, नेहा जुनेजा, बलविंदर कौर, शैली गुप्ता, जावेद अहमद सुलतान, कमलेश सिंह, विजय कुमर आदि बड़ी संख्या में बैंकर्स उपस्थित थे। कल सुबह 10 बजे पुनः 36 मॉल के सामने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। ऑल इंडिया इन्श्योरेंस एम्प्लाइज एशोसिएशन व इंडियन रेल्वे एम्प्लाइज फेडरेशन सहित विभिन्न संगठनों ने दो दिवसीय अखिल भारतीय बैंक हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया है। बैंकर्स क्लब बिलासपुर के समन्वयक ललित अग्रवाल ने आम जनता को दो दिवसीय हड़ताल से होने वाली असुविधा हेतु क्षमा याचना करते हुए जनहित में की गई हड़ताल को समर्थन देने के आग्रह किया है।

## आखिरकार लोनवि की जमीन बचा ली गई, अधीक्षक भू अभिलेख ने नामांतरण आदेश को परिमार्जित किया

पायनियर संवाददाता < बिलासपुर  
www.dailypioneer.com

पीडब्ल्यूडी की जमीन को एक भू माफिया द्वारा बेचे जाने और रजिस्ट्री कराने की शिकायत की जांच की गई तो मामला कुछ और निकला। अधीक्षक भू अभिलेख ने पाया कि ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि नुटिवाश और जानकारी के अभाव में हुआ था। भू-अभिलेख अधीक्षक ने नामांतरण आदेश को परिमार्जित करने के साथ ही पटवारी द्वारा दस्तावेज में सुधार भी कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि शहर से लगे ग्राम बहताराई के हल्का नम्बर 48 तहसील बिलासपुर में एक वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 310/2 जो कि वर्ष 1982 में लोनवि द्वारा बहताराई बिजौर मार्ग में अधिग्रहण किया गया था परन्तु वर्तमान रिकॉर्ड में कहीं भी सड़क की भूमि दर्ज नहीं थी जिसका फायदा उठाते हुए एक भूमाफिया ने उक्त जमीन की रजिस्ट्री करा ली तथा

अधिकारी द्वारा नामांतरण किया गया। उक्त नामांतरण खसरे में कहीं भी सड़क दर्ज नहीं होने के कारण नुटि किया गया तथा कई फजीलों को खड़ा करके पटवारी के विरुद्ध सड़क की भूमि बेचे जाने हेतु आवेदन कलेक्टर को देने तथा राजस्व मंत्री से पटवारी की शिकायत करने का कार्य भी किया गया। पटवारी व अधिकारियों पर उक्त मामले में सलिलता के आरोप लगाए गए जबकि पटवारी द्वारा उक्त नुटि हुए नामांतरण के विरुद्ध अधिकारियों के संज्ञान में उक्त बातें लाकर और पुनर्विलोकन हेतु अनुमति ली तथा जिस अधिकारी द्वारा उक्त नामांतरण पारित किया गया था उन्होंने 19/नवंबर/21 को उक्त नामांतरण के आदेश को परिमार्जित कर पुनः विक्रेता के नाम करने हेतु आदेश दिया। इस प्रकार पटवारी तथा अधिकारी द्वारा उक्त नुटि को सुधार लिया गया।

**नोडल अधिकारियों का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आज बिलासपुर।** पी.सी.पी.एन.डी.टी. अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति, जिला नोडल अधिकारियों, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, एवं आर.एम.एन.सी.एच. सलाहकार का संभाग स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक 17 दिसम्बर को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित की गई।

## छग साहित्य, कला एवं युवा महोत्सव का आयोजन, सौंपे गये दायित्व

पायनियर संवाददाता < बिलासपुर  
www.dailypioneer.com

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ लोक साहित्य, कला एवं युवा महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन 17 दिसम्बर को और संभाग स्तरीय आयोजन 22 से 24 दिसम्बर के बीच किया जायेगा। उक्त आयोजनों में आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे गये हैं। उक्त आयोजनों में पुलिस विभाग को आयोजन स्थल में सुरक्षा व्यवस्था हेतु आरक्षकों की ड्यूटी, नगर पालिक निगम को पेयजल की व्यवस्था आयोजन स्थलों में सफाई व्यवस्था सैनेटाइजेशन, लोक निर्माण विभाग को मुख्यमंच का निर्माण, आवश्यकतानुसार टेंट, साउण्ड एवं लाइट

व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग को कबड्डी एवं खो-खो विधाओं के लिए फर्स्ट एड सुविधा के साथ चिकित्सकर्मियों की ड्यूटी, प्रतिभागियों के लिए मास्क एवं सैनेटाइजेशन की व्यवस्था, खाद्य विभाग को प्रतिभागियों के लिए भोजन व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, परिवहन विभाग को निर्णायकों के लिए परिवहन हेतु चारपहिया वाहन की व्यवस्था, जनसंपर्क विभाग को संपूर्ण आयोजन की वीडियोग्राफी एवं प्रचार-प्रसार तथा आयोजन उपरान्त डी.वी.डी. में वीडियो उपलब्ध कराना, वाद-विवाद व निबंध हेतु विषय का चयन चित्रकला, गेंड़ी, भौंरा, फुगड़ी, हेतु निर्णायकों की नियुक्ति, व्यायाम अनुदेशकों की ड्यूटी की जिम्मेदारी दी गई है।

### नगरपालिका उप निर्वाचन, मतदान के लिए 20 को श्रमिकों को मिलेगा अवकाश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्र. 29 में सपन्न होने वाले पार्षद पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिवस 20 दिसम्बर को वार्ड क्र. 29 की सीमा में समस्त कारखानों, स्थापनाओं में कारखाना अधिनियम 1948 एवं दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आते हैं वहां कार्यरत श्रमिक, कर्मचारियों के लिए मतदान करने हेतु अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखानों जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे का अवकाश तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी गई है।

### समर्थन मूल्य में 1 लाख 33 हजार 657 मीट्रिक टन धान की खरीदी

बिलासपुर। विपणन वर्ष 2021-2022 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जिले में सुचारू रूप से संचालित है। अब तक 33 हजार 232 किसान खरीदी केन्द्रों में अपना धान बेच चुके हैं और उनको 2 करोड़ 60 लाख 29 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उठाव हेतु 95 हजार 494 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. राईस मिलर्स को जारी किया गया है। जिला विपणन अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि जिले में 16 दिसम्बर 2021 तक 133657.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी जा चुकी है। कुल पंजीकृत किसानों में से 28.29 प्रतिशत किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच चुके हैं। कुल पंजीकृत रकबे में से 32.40 प्रतिशत रकबे का धान किसानों द्वारा बेचा जा चुका है। इसी तरह राईस मिलर्स को 95 हजार 494 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। राईस मिलर्स द्वारा अब तक 57 हजार 239 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

### जनपद पंचायत सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

बिलासपुर। क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र नूतन चैक सरकार में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, जनपद सदस्यों, का आधारभूत प्रत्यासन्न विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें छग. पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम, जनपद पंचायत के कार्य दायित्व तथा कामकाज संचालन के नियम एवं प्रक्रिया, स्थायी समितियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 आदि विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में कोटा एवं तखतपुर जनपद पंचायतों के 18 सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने इस प्रशिक्षण को अपने लिए काफी उपयोगी एवं लाभदायक बताया। प्रशिक्षण पश्चात् अपने कर्तव्यों का उत्साह के साथ निर्वहन करने और अपने क्षेत्र के निवासियों को पंचायती राज की योजनाओं से लाभ दिलाने हेतु संकल्प किये गये प्रशिक्षण का समापन 15 दिसम्बर को किया गया। जिसमें प्राचार्य एवं अनुदेशक क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर तथा कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।

## भूपेश बघेल सरकार के बेमिसाल तीन साल गांव ,गरीबों और किसानों की सरकार

### भूपेश बघेल की सरकार ने जो कहा वह किया

किसानों का धान 25 सौ रुपये क्विंटल में लेने वाली देश की पहली सरकार

धान खरीदी और उठाव/परिवहन में अक्वल बिलासपुर जिला

- किसानों से निवेदन -

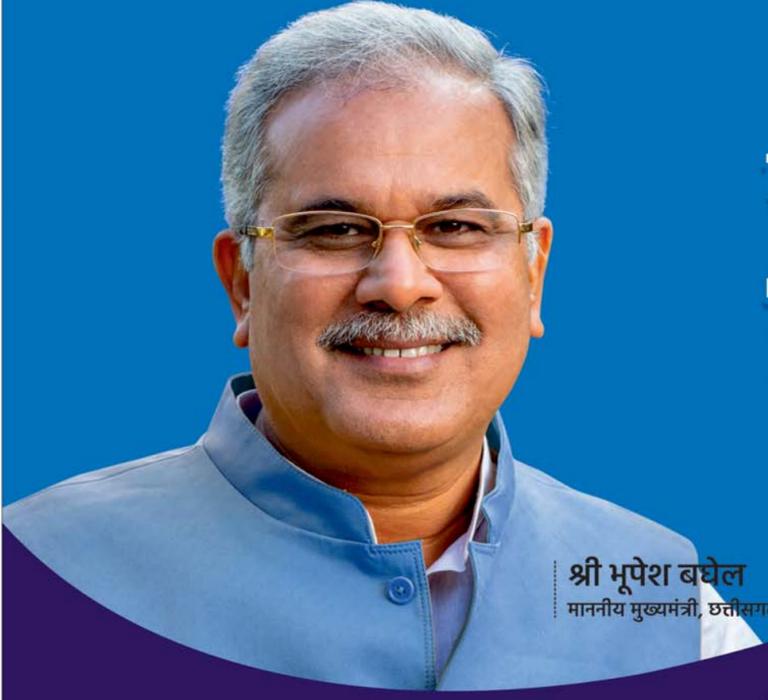
अपना धान पूरी तरह सुखाकर खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए लाएं

## गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

प्रमोद नायक

अध्यक्ष

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर



श्री भूपेश बघेल  
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

# न्याय, सरोकार व इच्छाशक्ति से बना छत्तीसगढ़ मॉडल

## » किसान

- ❖ कर्ज मुक्त किसान, अनुदान राशि से बढ़ी आय और पैदावार
- ❖ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता

## » पशुपालक

- ❖ सरकार द्वारा गोबर खरीदी से बढ़ती आय, खुले रोजगार के अवसर
- ❖ आर्थिक उन्नति ने बदली गांवों की तस्वीर

## » महिलाएं

- ❖ स्वास्थ्य एवं सुपोषण को दी प्राथमिकता
- ❖ बराबरी के अवसरों ने किया सशक्त

## » आदिवासी

- ❖ अधिग्रहित कृषि भूमि वापस लौटाई
- ❖ आदिवासियों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा के लिए गठित समिति

## » वनाश्रित

- ❖ जंगल जमीन पर दिलाये अधिकार
- ❖ देश में लघु वनोपजों की सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी

## » युवा

- ❖ युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर
- ❖ ई-पंजीकरण के माध्यम से निर्माण कार्यों में अवसर

## » पर्यावरण

- ❖ छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार स्वच्छतम राज्य का खिताब
- ❖ प्रतिदिन 1600 टन ठोस कचरे का वैज्ञानिक निपटान
- ❖ वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से वन क्षेत्र में इजाफा

## » शिक्षा

- ❖ विश्वस्तरीय स्कूलों से नई पीढ़ी को उज्ज्वल भविष्य के समान अवसर
- ❖ उच्च शिक्षा के नए गुणवत्तापरक केन्द्रों की स्थापना

## » स्वास्थ्य सेवाएं

- ❖ घर की चौखट तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं
- ❖ सभी आय वर्गों को रियायती दरों पर जेनेरिक दवाएं

## » खेल

- ❖ भविष्य के लिए प्रतिभासम्पन्न प्रतिभागियों का निर्माण
- ❖ खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व बेहतर प्रशिक्षण

## » उद्योग

- ❖ नई औद्योगिक नीति से समावेशी निवेश के खुले नए द्वार
- ❖ आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन

## » बिजली

- ❖ लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ
- ❖ बिजली से किसानों, वनाश्रितों व उद्योगों की बदल रही तस्वीर

## » शहरी विकास

- ❖ हर घर शुद्ध पेयजल
- ❖ मुख्यमंत्री मितान योजना से घर-घर तक पहुंच रही नागरिक सेवाएं
- ❖ झुग्गी झोपड़ी वासियों को मिला भूमि के स्वामित्व का अधिकार



S-30794/89

